

निहाल सिंह और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य

[के. सुब्बा राव, रघुबर दयाल, और जे. आर. मुधोलकर, जे. जे.]

उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त आपराधिक विचारण-प्रत्यर्पण आदेश-इस न्यायालय की तुलना में अपील को प्राथमिकता दी गई-इस न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई में इस न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-भारत का संविधान, अनुच्छेद 136

अपीलार्थियों ने खुद को एक गैरकानूनी सभा के रूप में गठित किया और अपने सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में दो व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बने। उन पर एस. एस. 148 और भारतीय दंड संहिता की 302/149 के तहत मुकदमा चलाया गया। निचली अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने पूरे साक्ष्य की समीक्षा पर, दोषमुक्ति के आदेश को दरकिनार कर दिया और उनमें से प्रत्येक को उपरोक्त आरोपों के तहत क्रमशः आजीवन और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसलिए यह अपील की गई है।

अभिनिर्धारित (सुब्बा राव और मुधोलकर जे. जे. के अनुसार) इस न्यायालय को तथ्यों और कानून पर संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील की सुनवाई करने का पूरा विवेकाधिकार है। लेकिन इस व्यापक अधिकार क्षेत्र को इस न्यायालय के अभ्यास द्वारा विनियमित किया जाना है। इस न्यायालय द्वारा इस तरह की अपील की सुनवाई के लिए दो तरीके हैं: एक है पूरे साक्ष्य को देखना द्वारा फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि क्या उच्च न्यायाधीशालय ने संवत सिंह के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन किया है या क्या अपील एक असाधारण है जो न्यायाधीश के हित में इस न्यायाधीशालय के हस्तक्षेप की मांग करती है। दूसरा और अधिक सुविधाजनक तरीका

यह है कि वकील को मामले को व्यापक रूप द्वारा बताने की अनुमति दी जाए और निचली अदालतों के फैसलों को देखने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जाए कि क्या अपील ऊपर उल्लिखित दो श्रेणियों में द्वारा एक या दूसरे के तहत आती है, और फिर, यदि अदालत संतुष्ट है कि यह पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, तो ऐसा करने के लिए।

दूसरी विधि अधिक सुविधाजनक है क्योंकि यह व्यावहारिक रूप से ऐसी अपील को नियमित अपील के रूप में मानने की वैकल्पिक स्थानीय प्रक्रिया को अपनाने में शामिल समय की अनावश्यक बर्बादी को भी रोकती है। जाहिर है कि यह न्यायालय इस संबंध में व्यवहार का एक अनम्य नियम निर्धारित नहीं कर सकता है और यह विभाजन पीठों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे उस प्रक्रिया का पालन करें जो उन्हें उपयुक्त लगे।

संवत सिंह. बनाम राजस्थान राज्य, [1961] 3 एस. सी. आर. 120 का पालन किया गया।

बॉम्बे राज्य बनाम रूसी मिस्री, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 391 का पालन किया गया।

(2) उच्च न्यायालय ने संवत सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा था और पूरे साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया था और तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचा था जैसा कि उसने किया था। यह कोई असाधारण मामला नहीं है जिसमें पूरे साक्ष्य की समीक्षा की जा सकती है।

(3) तथ्यों पर निजी बचाव का कोई मामला नहीं बनाया जा सका। यह याचिका निचली अदालत या उच्च निचली अदालत के समक्ष नहीं उठाई गई थी।

(जे. रघुबर दयाल के अनुसार) (1) अनुच्छेद 136 के तहत अपील की सुनवाई को दो भागों में विभाजित करना, व्यापक दृष्टिकोण पर सुनवाई और बाद में, यदि आवश्यक हो, तो तथ्यों पर सुनवाई करना, सुनवाई को उतना सही नहीं बनाता है जितना कि अपील के उचित निर्णय के लिए वांछनीय होगा।

(2) इस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के दायरे और इस प्रकृति की अपील की सुनवाई में अपने विवेकाधिकार के प्रयोग की सीमाओं के बारे में कोई सीमा निर्धारित करना वांछनीय नहीं है क्योंकि इस न्यायालय को तथ्यों और कानून दोनों पर अपील सुनने का पूरा विवेकाधिकार है।

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णय:की दाण्डिक अपीलीय सं 53/1962

पंजाब उच्च न्यायालय के दाण्डिक अपीलीय सं 1018/ 1960 के निर्णय और आदेश 9 जनवरी, 1961 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थियों के लिए ए. रंगनाथम चेट्टी और के. एल. अरोड़ा।

प्रतिवादी की ओर से बी. के. खन्ना और पी. डी. मेनन। 10 मई, 1963-सुब्बा राव जे. और मुधोलकर जे. का निर्णय सुब्बा राव जे. द्वारा सुनाया गया। दयाल जे. ने एक अलग राय दी।

सुब्बा राव जे.-

चंडीगढ़ में पंजाब के लिए न्यायिक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील का निर्देश दिया गया है, जिसमें दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फिरोजपुर के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है, जिसमें धारा 148 और एस. एस. 302/149 के तहत 5 अपीलार्थियों को आरोप से बरी कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता और उक्त धाराओं के तहत उन्हें दोषी ठहराना और उनमें से प्रत्येक को क्रमशः आजीवन और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा देना।

अभियोजन पक्ष के मामले को संक्षेप में कहा जा सकता है: 23 दिसंबर, 1959 को, 5 अपीलकर्ताओं ने खुद को एक गैरकानूनी सभा में गठित किया और अपने सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में गुरदित सिंह और उनके बेटे पाल सिंह की मृत्यु का कारण बने। उस तारीख को लगभग सूर्यास्त के समय, 7 पाँच अपीलकर्ता निहाल सिंह, अपीलकर्ता 1 के पिता बंता सिंह की हवेली में मौजूद थे। जब तारा सिंह अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, तो घातक हथियारों से लैस 5 अपीलार्थी हवेली से बाहर आए और उन पर हमला करने के उद्देश्य से उनका पीछा किया। उस समय पास के एक कुएँ में अपने मवेशियों को पानी पिला रहे रंजीत सिंह ने उन्हें तारा सिंह को न पीटने के लिए कहा। जब अपीलार्थी उनका पीछा कर रहे थे, तब तारा सिंह ने भी शोर मचाया। रंजीत सिंह के पिता गुरदित सिंह, गुरदित सिंह के दूसरे बेटे पाल सिंह और पाल सिंह के बेटे बलबीर सिंह भी तारा सिंह की आवाज़ सुनकर अपने घर से बाहर आ गए। पाल सिंह अपने हाथ में एक टेक ले जा रहे थे। गुरदित सिंह और पाल सिंह ने हमलावरों को तारा सिंह को न पीटने के लिए कहा। दलीप सिंह, अपीलकर्ता 3 ने पाल सिंह को पीछे से पकड़ लिया और निहाल सिंह, अपीलकर्ता 1 ने पाल सिंह के सिर पर एक डंग प्रहार किया। पाल सिंह ने दर्शन सिंह, अपीलकर्ता 4 के खिलाफ आत्मरक्षा में अपने तकवे का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अपीलकर्ता 5, हरबंस सिंह ने अपने तकवे से पाल सिंह को झटका दिया और बाद वाला गिर गया। इसके बाद, दर्शन सिंह और प्रीतम सिंह, अपीलकर्ता 2 ने पाल सिंह को अपने तकवे से दबाया जब पाल सिंह जमीन पर लेटे हुए थे। पाल सिंह के हाथ में टकवा उनके हाथ से नीचे गिर गया और उसके बाद उनके पिता गुरदित सिंह ने उसे जब्त कर लिया और अपीलार्थियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने का प्रयास किया; प्रीतम सिंह ने गुरदित सिंह के सिर पर एक डंग मारा। हरबंस सिंह और दर्शन सिंह ने भी ऐसा ही किया। गुरदित सिंह की मौके पर ही मौत हो गई

और उसके कुछ ही समय बाद पाल सिंह की मौत हो गई। अपीलार्थी उपरोक्त प्रभारों को पूरा करने के लिए सत्रों के प्रति प्रतिबद्ध थे।

अपीलकर्ताओं ने आरोपों के लिए "दोषी नहीं" होने का अनुरोध किया और कहा कि उन सभी को शत्रुता के कारण फंसाया गया था। विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ अपने मामले को सभी तरह के संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और उस निष्कर्ष पर, उन सभी को बरी कर दिया। अपील पर, उच्च न्यायालय, पूरे साक्ष्य की समीक्षा पर, एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा: इसने अभिनिर्धारित किया कि विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के गवाहों को बदनाम करने में और उस निष्कर्ष पर पूरी तरह से गलत था। इसने अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और उन्हें उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई। इसलिए याचिका दायर की गई है।

इस न्यायालय ने संवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1) मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने के आदेश के खिलाफ अपील के निपटारे के तरीके को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया।

"पूर्वगामी चर्चा से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं: (1). एक अपीलीय न्यायालय है। उन साक्ष्यों की समीक्षा करने की पूर्ण शक्तियाँ, जिन पर दोषमुक्ति करने का आदेश स्थापित किया गया है; (2) शिव स्वरूप के मामले में निर्धारित सिद्धांत (1) ऐसी अपील के निपटारे में किसी मामले में न्यायालय के दृष्टिकोण के लिए एक सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं; और (3) इस न्यायालय के निर्णयों में उपयोग किए गए विभिन्न वाक्यांश, जैसे कि (1) पर्याप्त और सम्मोहक कारण, (ii) "अच्छे और पर्याप्त ठोस कारण", और (ii) "मजबूत कारण" का उद्देश्य

अपील में अपील न्यायालय की निस्संदेह शक्ति को कम करना नहीं है। 'दोषमुक्ति' को संपूर्ण साक्ष्य की समीक्षा करने और 'अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने' के लिए; लेकिन ऐसा करते समय उसे न केवल तथ्य के प्रश्नों और उन तथ्यों पर निष्कर्ष पर पहुंचने में अपने दोषमुक्ति के आदेश के समर्थन में नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर असर डालने वाले रिकॉर्ड पर प्रत्येक मामले पर विचार करना चाहिए, बल्कि अपने निर्णय में उन कारणों को भी व्यक्त करना चाहिए जो उसे यह ठहराने के लिए प्रेरित करते हैं कि दोषमुक्ति उचित नहीं थी।”

लेकिन अधिक कठिन प्रश्न यह है कि इस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के दायरे को परिभाषित करना और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील में अपने विवेकाधिकार के प्रयोग की सीमा को परिभाषित करना है, जिसमें एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आदेश को दरकिनार करने के बाद एक अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था। संविधान के अनुच्छेद 136 को व्यापक वाक्यांश में जोड़ा गया है यह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल अपने विवेक से सीमित है। इसलिए, यह अपने विवेकाधिकार पर एक अपील को स्वीकार कर सकता है और उसमें उल्लिखित निर्णयों, फरमानों, निर्णयों, वाक्यों या आदेशों के संबंध में एक अपीलीय न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है 'इसका मतलब है कि, इस न्यायालय को निस्संदेह उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी करने वाले अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए एक अपील में तथ्य के निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन इस व्यापक अधिकार क्षेत्र को इस न्यायालय के अभ्यास द्वारा विनियमित किया जाना है। यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश को दरकिनार करते हुए संवत सिंह के मामले में इस

न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, निश्चित रूप से इस न्यायालय के उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का आधार हो सकता है। लेकिन यदि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए साक्ष्य पर विचार किया है और उस पर तथ्य के निष्कर्ष दिए हैं, तो हम सोचते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपीलों में तथ्य के निष्कर्षों के संबंध में इस न्यायालय में प्राप्त वही प्रथा आसानी से अपनाई जा सकती है। बॉम्बे राज्य बनाम रूसी मिस्त्री (2) में इस न्यायालय ने आपराधिक अपीलों 395 में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के विनियमन के संबंध में इस न्यायालय में प्राप्त प्रथा को दर्ज किया है।

संविधान का अनुच्छेद 136 किसी भी पक्ष को न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह उच्चतम न्यायालय को उपयुक्त मामलों में हस्तक्षेप करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। यह है विवेकाधीन शक्ति में निहित है कि इसे पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसका स्पष्ट रूप से ऐसा अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि यह उस पक्ष को अधिकार प्रदान करता है जिसके पास कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है। प्रिवी काउंसिल और उसके बाद संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तथ्य के प्रश्नों पर हस्तक्षेप करने का अभ्यास असाधारण मामलों को छोड़कर नहीं है, जब निष्कर्ष ऐसा होता है कि "यह न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है" या "कानूनी प्रक्रिया के रूपों की अवहेलना करके या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कुछ उल्लंघन या अन्यथा पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है।

यही प्रथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने के आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा करने में इस न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग को भी नियंत्रित कर सकती है। संक्षेप में कहा

गया है, आम तौर पर यह न्यायालय दो प्रश्नों को संबोधित करता है जब ऐसी अपील निपटान के लिए उसके सामने आती है, अर्थात्, (i) क्या अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना करने में संवत सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया था; और (ii) यदि उसने किया, तो क्या यह उन असाधारण मामलों में से एक है जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करता है। इस तरह की अपील करने के दो तरीके हैं: एक है पूरे साक्ष्य को देखना जैसा कि यह न्यायाधीशालय एक नियमित अपील में करता है द्वारा फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या उच्च न्यायाधीशालय ने संवत सिंह के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन किया है या यह पता लगाने के लिए कि क्या अपील एक असाधारण है जो न्यायाधीश के हित में इस न्यायाधीशालय के हस्तक्षेप की मांग करती है। दूसरा और अधिक सुविधाजनक तरीका यह है कि वकील को मामले को व्यापक रूप द्वारा बताने की अनुमति दी जाए और, निचले न्यायालयों के निर्णयों को देखने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या अपील ऊपर उल्लिखित दो श्रेणियों में द्वारा एक या अन्य के तहत आती है और फिर, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि यह पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, तो ऐसा करने की अनुमति दी जाए। जाहिर है कि यह न्यायालय इस संबंध में व्यवहार का एक अनम्य नियम निर्धारित नहीं कर सकता है और यह उन खंडपीठों पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो ऐसी अपीलों से निपटने के लिए उस प्रक्रिया का पालन करें जो उन्हें उपयुक्त लगे। लेकिन यह अवलोकन करना अनुचित नहीं हो सकता है कि हमारे विचार में दूसरा तरीका अधिक उपयुक्त या किसी भी तरह से अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि यह इस न्यायाधीशालय को एक उचित मामले में न्यायाधीश करने में सक्षम बनाता है, लेकिन यह व्यावहारिक रूप से ऐसी अपील को नियमित अपील के रूप में मानने की वैकल्पिक प्रक्रिया को अपनाने में शामिल समय की अनावश्यक बर्बादी को भी रोकता है।

आइए अब हम उक्त दृष्टिकोण से पक्षों की दलीलों को देखें। अभियोजन पक्ष की कहानी को तीन चश्मदीद गवाहों, रंजीत सिंह (पीडब्ल्यू 2), सौदागर सिंह (पीडब्ल्यू 3) और बलबीर सिंह (पीडब्ल्यू 4) और बलवंत सिंह, सरपंच (पीडब्ल्यू 7) द्वारा बयान दिया गया था, जो कथित तौर पर घटना के तुरंत बाद मौके पर गए थे। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हथियारों के उत्पादन द्वारा भी इस मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने की कोशिश की जाती है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर साक्ष्य को खारिज कर दिया: (1) बंता सिंह की हवेली और घटना स्थल के बीच की दूरी 17 करम है। उदाहरण के लिए, लगभग 85 फीट, और घटना स्थल और पाल सिंह के घर के द्वार के बीच 22 कराम, यानी लगभग 110 फीट है, और इसलिए यह संभव नहीं है कि हमलावरों और मृतक व्यक्तियों के बीच का प्रभाव टकराव के स्थान पर हुआ हो जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा वर्णित है। (2) जिस समय हत्याएं की गईं, वह लगभग रात 9 बजे थी और सूर्यास्त का समय नहीं था, जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा वर्णित किया गया है, क्योंकि (ए) चिकित्सा साक्ष्य से पता चला है कि लगभग 2 पाउंड का अर्ध-पचाया हुआ भोजन था। गुरगित सिंह के पेट में और उनके मूत्राशय में 12 औंस मूत्र भी, जो इंगित करता है कि भोजन करने के बाद सोते समय उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी; (बी) पी. डब्ल्यू. के रूप में। 1 महिला चिकित्सक ने कहा है कि दो मृत व्यक्तियों को लगी चोटों और उनकी मृत्यु के बीच की संभावित अवधि लगभग 4 या 5 घंटे थी; यह परिस्थिति इस बात के सबूत के विपरीत है कि उन्होंने घायल होने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया; (सी) घटना के गांव और पुलिस स्टेशन मल्लन वाला के बीच की दूरी लगभग 61 मील है और इसलिए पी. डब्ल्यू. 2 जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दी थी, उसे हाल ही में लगभग 9 पूर्वाह्न पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए था, लेकिन वास्तव में रिपोर्ट 24 दिसंबर, 1959 को लगभग 12.45 सुबह दर्ज की गई थी। (3) (क) जबकि पीडब्ल्यू 2 ने कहा कि मृतक गुरदित सिंह ने

निहाल सिंह के सिर पर तकवा मारा था, डॉक्टर की जांच से यह पता नहीं चला कि निहाल सिंह के सिर पर कोई चोट लगी थी, लेकिन उनके बाएं अंगूठे के पीछे केवल "1/2x1/8" था। (ख) जबकि पीडब्लू 3 ने कहा कि मृतक गुरदित सिंह ने दलीप सिंह के खिलाफ तकवा का इस्तेमाल किया था, डॉक्टर उस हथियार की प्रकृति बताने की स्थिति में नहीं था जिससे उसे चोट लगी थी।(4) दलीप सिंह के पास कोई हथियार नहीं होने के कारण अभियोजन पक्ष को उसका नाम गलत तरीके से पेश करना चाहिए था। (5) पी. डब्ल्यू. 7 ने जिरह में कहा कि वह यह नहीं कह सकते कि चौक के पास दो स्थानों पर पाया गया खून एक माशा या उससे अधिक था और इसने घटना स्थल पर दो व्यक्तियों की हत्या की कहानी को नकार दिया। और (6) अलग-अलग गवाहों के साक्ष्य के बीच मामूली विवरणों में विसंगतियां हैं।

उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट था कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य के छोटे पहलुओं के महत्व को बढ़ाया और इसकी बुनियादी विशेषताओं को कम या नजरअंदाज कर दिया। संवत सिंह के मामले (1) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य पर फिर से विस्तार से विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी को दोषी ठहराया था। उस दृष्टिकोण पर, उच्च न्यायालय ने, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।

अपीलार्थियों की ओर से श्री ए. रंगनाथम चेटी ने तर्क दिया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य के बारे में एक उचित दृष्टिकोण अपनाया था और उच्च न्यायालय ने उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों की सराहना नहीं करके गलत तरीके से एक अलग दृष्टिकोण अपनाया था जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के साथ भारी थीं और साक्ष्य के आधार पर, निजी बचाव का एक स्पष्ट मामला बनाया गया है।

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील करने वाली महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूरियों को ध्यान में रखते हुए मृतक की हत्या उस स्थान पर नहीं की जा सकती थी जहां गवाहों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनकी हत्या की गई थी। यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो समय और दूरी और गवाहों की गतिविधियों के आधार पर यह तर्क अत्यधिक काल्पनिक और कृत्रिम है, इस सरल कारण से कि किसी भी गवाह से ऐसी वैज्ञानिक विवरण में वर्णन करने की उम्मीद करना असंभव है, जो गणना की कसौटी पर खरा उतर सके। लेकिन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यही किया और इसे उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया।

अगली परिस्थिति जिस पर दृढ़ता से भरोसा किया गया है वह है पाल सिंह के मृत शरीर पर पाए गए कीट के काटने। महिला चिकित्सक डॉ. बलबीर कौर ने शव की अपनी पोस्टमॉर्टम जांच में पाया कि "दोनों नथुने, निचले होंठ और माथे पर कीट के काटने का निशान था।" पुलिस अधिकारी उधम सिंह ने अपने चोट के बयान में उक्त चोटों को "नाक, निचले होंठ, दाहिने गाल और बाईं आंख के ढक्कन पर चूहे जैसे किसी जानवर के काटने के निशान" के रूप में वर्णित किया। महिला चिकित्सक के विवरण को अधिक सटीक माना जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मृतक पाल सिंह के चेहरे पर किसी कीट के काटने का निशान था। तर्क यह है कि कोई भी चूहा या कीट उस कमरे में मृत शरीर को नहीं काट सकता था जिसमें उसे रखा गया था जब प्रकाश जल रहा था, जब वह ढका हुआ था और जब इतने सारे लोग उसके बगल में मौजूद थे, और इसलिए, उक्त काट किसी चूहे या चूहे के कारण हुआ होगा जब मृतक रात लगभग 9 बजे खेत में स्थापित गन्ना-क्रशर के पास सो रहा था। यह सच है कि इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि गन्ना-क्रशर खरीदा गया था, हालांकि इसे स्थापित नहीं किया गया था और यह रंजीत सिंह के घर के पीछे लगभग 5 से 6 मरला की खाली जगह में था। लेकिन इससे यह एक अनुचित निष्कर्ष होगा कि गवाह सच नहीं बोल रहे थे। हम किसी

कीट या चूहे के कपड़े के नीचे आकर शव को ढकने और उसे काटने में कोई असंभवता नहीं देखते हैं।

एक अन्य परिस्थिति जिसे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा बढ़ाया गया है, वह है पोस्टमॉर्टम के समय 2 पाउंड से कम की खोज। मृतक गुरदित सिंह के पेट में अर्ध-पचाया हुआ भोजन और मूत्राशय में 12 औंस मूत्र ऐसा कहा जाता है कि यह परिस्थिति दर्शाती है कि उक्त मृतक ने अपना भोजन ले लिया होगा और जब उसकी हत्या की गई थी तब वह सो रहा होगा, क्योंकि अगर उसकी हत्या शाम 5:30 बजे की गई होती, जैसा कि गवाहों ने गवाही दी थी, तो मृतक के पेट में इतना अर्ध-पचाया हुआ भोजन या उसके मूत्राशय में इतनी बड़ी मात्रा में मूत्र नहीं होता। उच्च न्यायालय ने कहा कि उक्त परिस्थितियाँ मृत्यु के समय का पता लगाने का एक विश्वसनीय आधार नहीं दे सकती हैं, विशेष रूप से जब रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मृतक ने एक जोड़े के लिए कोई भोजन नहीं लिया था। उस पर हमला होने से कुछ घंटे पहले। इस तथ्य के अलावा कि भोजन को पचाने के लिए आवश्यक समय लिया गया भोजन की प्रकृति, संबंधित व्यक्ति की पाचन क्षमता और किसी विशेष समय पर उसके स्वास्थ्य के आधार पर भिन्न होता है, इस तरह के साक्ष्य पर भरोसा करना भी संभव नहीं है जब तक कि कुछ निश्चित प्रमाण न हों कि मृतक ने अपनी मृत्यु से कुछ घंटों के भीतर कोई पर्याप्त भोजन नहीं लिया था। इस तरह के निश्चित आंकड़ों के बिना, अदालत ग्रामीणों की दोपहर 1 बजे दोपहर का भोजन और शाम 7 बजे रात का भोजन करने की सामान्य आदत पर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं आ सकती है। सामान्य से अधिक समय तक मूत्र को बनाए रखने की क्षमता व्यक्तिगत आदतों पर निर्भर करती है। इसके अलावा मामले के इस पहलू को डॉक्टर की प्रतिपरीक्षा में आगे नहीं बढ़ाया गया था और उक्त दो कारकों के आधार पर उससे कोई सवाल नहीं किया गया था।

इसलिए, उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्णय सही था कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उक्त परिस्थितियों को अनुचित महत्व देने में गलत थे।

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने फिर से डॉ. बलबीर कौर के बयान पर भरोसा किया। इस प्रभाव से कि मृतक को चोट पहुँचाने और उनकी मृत्यु के बीच की अवधि 4 या 5 घंटे हो सकती है और यह निष्कर्ष निकाला कि गवाह सच नहीं बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि मृतक ने मौके पर या चोट लगने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में कहा कि गुरदित सिंह के मामले में चोटें पोस्टमार्टम की प्रकृति की थीं और चोट लगने और मौत के बीच का संभावित समय कुछ घंटे या उससे अधिक था और पाल सिंह के मामले में भी उसने कहा कि चोट लगने और मौत के बीच का संभावित समय कुछ घंटे था। यह साक्ष्य केवल एक अनुमान था और न तो सटीक होने का इरादा था और न ही यह किसी वैज्ञानिक डेटा पर आधारित था। उसका मतलब केवल यह था कि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर मौत हो गई थी। इस तरह की गंजी राय निश्चित रूप से मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य से अधिक नहीं हो सकती थी। इस तर्क के समर्थन में कि हत्या रात में की गई होगी, पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कथित देरी के संबंध में कुछ तर्क दिए गए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार हत्या शाम 5:30 पूर्वाह्न की गई थी; अगले दिन सुबह 12.45 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आधी रात के ठीक बाद। इससे यह कहा जाता है कि घटना स्थल और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी केवल 6-1/2 मील है और यह दिखाने के लिए कुछ सबूत हैं कि पक्ष घोड़ों पर गए थे और रिपोर्ट देने में देरी इस मामले का समर्थन करती है कि हत्या केवल रात में की गई होगी। इसे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि मामले की परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में न तो अनावश्यक रूप से देरी की गई थी और न ही अनावश्यक रूप से। रंजीत सिंह ने साक्ष्य में कहा कि उसने पुलिस स्टेशन जाने में

घोड़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सड़क उनका उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं थी और गवाहों ने यह भी कहा कि वे चारों ओर घूम रहे अभियुक्तों द्वारा देखे बिना चुपचाप जाना चाहते थे। इन परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि इस आधार पर साक्ष्य को बदनाम करने में कोई देरी नहीं हुई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मनगढ़ंत थी और साक्ष्य को इस तरह से आकार दिया गया था कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए संस्करण में फिट हो।

प्रत्यक्षदर्शी को बदनाम करने में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया एक और तथ्य यह है कि गवाहों ने कहा कि मृतक ने निहाल सिंह के सिर पर तकवा मारा था, लेकिन चिकित्सा जांच में उनके बाएं अंगूठे पर केवल एक छोटा सा खरोंच दिखाई दिया। उच्च न्यायालय ने समझाया कि गवाहों को केवल अपने हथियारों के साथ अभियुक्तों की गतिविधियों का वर्णन करना चाहिए और वे स्पष्ट रूप से इस बात का सबूत नहीं दे सकते कि कोई विशेष हथियार शरीर को कहाँ मारा गया, क्योंकि यह न केवल व्यक्तियों के हथियार चलाने के तरीके पर निर्भर करेगा, बल्कि पीड़ित की गतिविधियों पर भी निर्भर करेगा। सिर पर एक प्रहार, यदि पीड़ित एक तरफ चला जाता है, तो पीड़ित का शरीर पूरी तरह से छूट सकता है या उसके शरीर के किसी ऐसे हिस्से पर गिर सकता है जो उसके लक्ष्य से अलग हो। उच्च न्यायालय ने जो कहा, उसमें निश्चित रूप से बल है।

तब यह कहा गया कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के अनुसार अभियुक्तों ने तारा सिंह के खिलाफ उनका उपयोग करने के उद्देश्य से अपने हथियार उठाए थे और वास्तव में उन्हें घेर लिया था और यदि उस कथन को बरकरार रखा जाता है, तो तारा सिंह के लिए बाल-बाल बचना असंभव था। यदि ऐसा है, तो तर्क आगे बढ़ता है, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिया गया बयान गलत होना चाहिए। यह तर्क अंग्रेजी अभिव्यक्ति "चारों ओर" पर बनाया गया है, जिसका अनुवाद पंजाबी भाषा में एक

संबंधित शब्द से किया गया है। हमें बताया जाता है कि पंजाबी अभिव्यक्ति का अर्थ "पीछा किया" भी होगा। चाहे वह हो, उस पर कोई तर्क नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि इस संदर्भ में, गवाहों का मतलब केवल यह हो सकता था कि आरोपी ने तारा सिंह का पीछा किया था।

हम उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा से लिए गए हैं। हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने संवत सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा है और पूरे साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचा है। हम सामान्य प्रथा से अलग होने और साक्ष्य की फिर से समीक्षा करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं देखते हैं।

फिर यह तर्क दिया जाता है कि पाए गए तथ्यों पर निजी बचाव का मामला बनाया गया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि निजी बचाव की याचिका को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष या अपील पर उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं लिया गया है। न ही पाए गए तथ्यों पर इस तरह की याचिका का कोई आधार है। तर्क मुख्य रूप से चश्मदीद गवाहों द्वारा घटना के विवरण पर आधारित है। पी. डब्ल्यू. 2 ने इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया:

"जब आरोपी अभी भी तारा सिंह का पीछा कर रहे थे, मेरे पिता गुरदित सिंह और भाई पाल सिंह अपने घर से बाहर आ गए, पाल सिंह एक तकवे के साथ।

जब गुरदित सिंह और पाल सिंह अपने घर से बाहर आए तो उन्होंने आरोपी से तारा सिंह को न पीटने का अनुरोध किया। गुरदित सिंह और पाल सिंह की इन बातों को सुनकर आरोपी दलीप सिंह ने पाल सिंह को पीछे से पकड़ लिया। उस समय आरोपी निहाल सिंह ने पाल सिंह

के सिर पर प्रहार किया, फिर पाल सिंह ने आरोपी दर्शन सिंह के खिलाफ आत्मरक्षा में अपने तकवे का इस्तेमाल किया। इसके बाद, आरोपी हरबंस सिंह ने पाल सिंह को उसके कुंद पक्ष का उपयोग करके एक तकवा मारा।”

यह तर्क दिया जाता है कि तारा सिंह के हमलावरों के हमलों से बच निकलने के बाद, दर्शन सिंह ने पीछे से पाल सिंह का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद पाल सिंह ने अपने तकवे का इस्तेमाल किया और आत्मरक्षा में अभियुक्तों ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया। इस तर्क को इस धारणा पर संबोधित किया गया था कि पाल सिंह के सिर पर कोई तकवा प्रहार नहीं किया गया था और आरोपी ने केवल पाल सिंह को पकड़ लिया था। यदि ऐसा था, तो तर्क आगे बढ़ा, पाल सिंह अपने तकवे का उपयोग करने में आक्रामक थे और इसलिए, अभियुक्तों को अपना बचाव करने का अधिकार था। अगर हम इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करते हैं, तो हम सबूतों को गलत तरीके से पढ़ रहे होंगे। आरोपी दलीप सिंह ने पाल सिंह को पीछे से पकड़ लिया जिससे निहाल सिंह उसे एक झटका देने में सक्षम हो गया। दलीप सिंह की उक्त हरकत और निहाल सिंह द्वारा पाल सिंह को दिए गए तत्काल प्रहार के बाद अन्य अभियुक्तों द्वारा किए गए प्रहार निजी बचाव के तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। अभियुक्त निश्चित रूप से आक्रामक थे और इस मामले में निजी बचाव का कोई सवाल ही नहीं उठेगा।

अंत में यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने मृतक की हत्या के लिए अभियुक्त का कोई सामान्य उद्देश्य स्थापित नहीं किया है और इसलिए, उच्च न्यायालय ने उन्हें एस. एस. 302/149 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराते हुए गलत किया। ऐसा कहा जाता है कि सबूतों में कुछ भी नहीं बताया गया है कि आरोपी तारा सिंह या उसके बचावकर्ताओं को मारने के लिए इंतजार कर रहे थे, कि घटना अचानक विकसित हुई और इसलिए दोनों मृतकों में से किसी को भी मारने का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं

है। लेकिन साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सभी अभियुक्तों ने दोनों मृतकों को गंभीर चोट पहुँचाने में सक्रिय भाग लिया था। आरोपी-3 ने पाल सिंह को पीछे से पकड़ लिया, आरोपी-1 ने उसके सिर पर डांग मारा, आरोपी-5 ने उस पर तकवा मारा और पीड़ित के नीचे गिरने के बाद आरोपी-2 और 4 ने उसे जमीन पर लेटे हुए सोती से मारा, इसलिए भी आरोपी-2 ने गुरदित सिंह के सिर पर डांग मारा। आरोपी-5 ने उसे तकवा मारा और गुरदित सिंह के गिरने के बाद आरोपी-4 ने उसे सोती से मारा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सभी आरोपी घातक हथियारों से लैस थे और जैसे ही तारा सिंह आए वे उस पर दौड़े और जब मृतक उसे बचाने आया तो उन्होंने संयुक्त रूप से उन हथियारों का इस्तेमाल किया और उन्हें गंभीर चोटें पहुँचाईं जो उनकी तत्काल मौत में समाप्त हो गईं। इन परिस्थितियों में मृतक को मारने का उद्देश्य साक्ष्य के आधार पर बड़ा लिखा गया था। इस तर्क में कोई बल नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

रघुबर दयाल जे.-सहमत हैं कि अपील खारिज कर दी जाए। हालाँकि, मैं ऐसी अपीलों पर न्यायालय के दृष्टिकोण के बारे में बताता हूँ। मैं किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने के आदेश को दरकिनार करने के बाद किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अनुच्छेद 136 के तहत अपील में इस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के दायरे और अपने विवेकाधिकार के प्रयोग की सीमाओं के बारे में कोई सीमा निर्धारित करना वांछनीय नहीं समझता। अनुच्छेद 136 के तहत न्यायालय के विवेकाधिकार का पूरा प्रयोग पूरी तरह से तथ्यों और कानून के आधार पर एक निश्चित अपील का निर्णय लेने वाली एक विशेष पीठ के विचारों पर निर्भर है और यह उस पीठ के लिए है कि उस अपील की सुनवाई और निर्णय के लिए कैसे आगे बढ़ना है। मेरे विचार से ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए एक निश्चित पीठ को

जो एक बेहतर तरीका प्रतीत होता है और निम्न न्यायालय के आदेश में कब हस्तक्षेप करना है, उसे निर्धारित करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

यह स्वीकार किया जाता है कि इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व्यापक है। यदि वह निश्चित और समान हो तो आम तौर पर कोई व्यक्ति न्यायालय की प्रथा के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अलग-अलग पीठों ने अलग-अलग तरीके से आगे बढ़े और अपील पर उनका उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अलग था। हरनाम सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है।

यह वास्तव में विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ के लिए है कि वह यथासंभव पूरी तरह से विचार करे कि क्या मामला इस न्यायालय में सुनवाई के योग्य है; यदि वह सुनवाई के योग्य है कि क्या यह कानून या तथ्य के किसी विशेष पहलू तक सीमित है और इसलिए यदि पीठ विशेष अनुमति देती है, तो उसे उन मामलों को स्पष्ट करना चाहिए जिन पर वह इस न्यायालय में सुनवाई को वांछनीय या आवश्यक समझती है। यदि ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जाता है, तो मैं चाहूंगा कि अपील की सुनवाई तथ्यों और कानून दोनों पर की जाए। बेशक हर कोई इस बात पर सहमत है कि अपील की सुनवाई कानून के बिंदुओं पर की जानी है। कुछ आम सहमति भी है कि किसी को उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों में हल्के से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मामले में हमेशा अलग दृष्टिकोण के लिए व्यापक गुंजाइश होती है। बेहतर होगा कि पार्टियों के वकील को पहले से पता होना चाहिए कि किन बिंदुओं पर सुनवाई की जाएगी ताकि वे उन बिंदुओं पर तैयार होकर आ सकें। अब मेरे दिमाग में जो होता है, वह यह है कि वकील आमतौर पर कानून के प्रश्नों के लिए तैयार रहते हैं। हालाँकि, अपीलार्थी का वकील न्यायालय को तथ्य के प्रश्नों में जाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है और जब भी वह सफल होता है तो उसके बाद

उसके पास बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। हालाँकि, प्रत्यर्थी के वकील को अनजान माना जाता है। वह तथ्यों पर अपीलकर्ता से मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। वह अदालत की मदद करने के लिए परिस्थितियों में अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, और यह बहुत कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अनुच्छेद के तहत अपील की सुनवाई को दो भागों में विभाजित करना, व्यापक दृष्टिकोण पर सुनवाई और बाद में, यदि आवश्यक हो, तो तथ्यों पर, सुनवाई को उतना सही नहीं बनाता है जितना कि अपील के उचित निर्णय के लिए वांछनीय होगा। यदि पक्षकारों को पता है कि एक बार जब वे बिना किसी सीमा के विशेष अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तो वे तथ्यों पर बहस करने के लिए स्वतंत्र होंगे, वे तैयार होकर आएंगे और अपने मुवक्किलों के लिए मामले को यथासंभव सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करेंगे, और न्यायालय भी निर्णय लेने के लिए बेहतर स्थिति में होगा।

बेशक, अपील को पूरी तरह से सुनने के बाद, यह न्यायालय इस बारे में सबसे अच्छी स्थिति में है कि अपील का निपटारा कैसे किया जाए। यह निश्चित रूप से केवल यह कहकर इसका निपटारा कर सकता है कि वह तथ्य के निष्कर्षों को गलत मानने का कोई कारण नहीं देखता है या वह उन निष्कर्षों पर विचार कर सकता है और एक अलग राय व्यक्त कर सकता है।

हालाँकि, जैसा कि पहले कहा गया है, मैं इस न्यायालय द्वारा इस तरह की अपील की सुनवाई कैसे की जाए, इस संबंध में कुछ भी व्यक्त नहीं करना चाहूंगा, जब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय को तथ्यों और कानून पर अपील की सुनवाई करने का पूरा विवेकाधिकार है और इसी तरह के कारण से यह निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय को एस 423 सीआर.पी. सी. के तहत दोषमुक्ति के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय साक्ष्य की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है। अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।